कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? आपने दो के बारे में मना कर दिया है और एक अवेंटिस के बारे में कहा है कि हमको इसकी दो शिकायतें प्राप्त हुईं। उसकी एन.पी.पी.ए. द्वारा जांच कराई गई और दोषी पाया है। उसके बाद आप ने केस को सी.बी.आई. को क्यों नहीं दिया ?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर, उसमें टैक्नीकल नुक्श था। उन्होंने दो की करवा ली—एक ही किस्म का पैक था, एक ही किस्म का इंसुलिन थी। पहले चार का था, टैक्नीकली चार्ज वही करते रहें, लेकिन उन्होंने किया नहीं। नोटिस दिया है और उस पर एज पर रूल एक्शन लिया जाएगा।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, मैंने पूछा था कि कौन-कौन से उत्पाद हैं ? दूसरे मैं यह कह रहा हूं कि इसकी जांच कब की गयी और एन.पी.पी.ए. द्वारा कब दोषी पाया गया ? फिर वह केवल सी.बी.आई. को क्यों नहीं दिया ?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : सर, सी.बी.आई. का तो केस ही नहीं है। यह तो टैक्नीकल नुक्श था। अब उसको नोटिस दिया है और 30 मई तक जवाब मांगा है। हम उस पर एक्शन लेंगे।

SHRI EDUARDO FALEIRO : Sir, I would like to put just one question. There are a lot of countries, including the United States, the U.S. Department of Commerce which are trying to bring pressure on India to remove the Drug Price Control Orders (DPCO), so that the prices of foreign drugs can go up. This will wreak havoc with our health system. Our poor people will die. Will the Minister assure us that he will not yield to such pressures; and, on the contrary, he will strengthen the DPCO so that the people in this country, particularly the poor people, at least, have the right to live?

SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA : Sir, I assure the House, डी०पी०सी०ओ० खत्म नहीं होगा और जो आम पब्लिक के लिए यूज होगा, वह इसके कंट्रोल में ही रहेगा।

श्री सभापति : क्वैश्चन नं० 505.

मुक्त विश्वविद्यालय

* 505. प्रो० रामबख्श सिंह वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) उक्त विश्वविद्यालयों में से कितने विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार तथा कितने राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में कोई अन्य मुक्त विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारत में 11 मुक्त विश्वविद्यालय हैं जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी शामिल है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1985 में की गयी थी। अब तक स्थापित मुक्त विश्वविद्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) 10वीं योजना के प्रस्तावों (2002-2007) में देश में आठ नए राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को खोलने का प्रावधान है।

विवरण

1.	**संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय**		**स्थापना वर्ष**
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली		1985
2.	**राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का नाम**	**राज्य का नाम**	**स्थापना वर्ष**
	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	1982
	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	राजस्थान	1987
	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना	बिहार	1987
	यशवन्तराव चवन महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	महाराष्ट्र	1989

राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का नाम	राज्य का नाम	स्थापना वर्ष
एम. पी. भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	1991
डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	गुजरात	1994
कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक	1996
नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1997
यू.पी. राजर्षी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1998
तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु	2002

Open University

†*505. PROF. R.B.S. VARMA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the total number of open universities established in India;

(b) the details of the open universities established by the Central Government as well as State Government out of the said universities;

(c) whether Government propose to establish any other open university in near future; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI) : (a) and (b) There are 11 Open Universities in India, including Indira Gandhi National Open University (IGNOU) which has been set up in 1985 under an Act of Parliament. A statement giving the details of Open Universities established so far is given in the enclosed statement. (*See* below)

(c) and (d) The 10th Plan proposals (2002–2007) envisage opening of eight new State Open Universities in the country.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

1.	**Open University set up under Act of Parliament**		**Year of Establishment**
	Indira Gandhi National Open University, New Delhi		1985
2.	**Name of State Open University**	**Name of State**	**Year of Establishment**
	Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad	Andhra Pradesh	1982
	Vardhaman Mahaveer Open University, Kota	Rajasthan	1987
	Nalanda Open University, Patna	Bihar	1987
	Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik	Maharashtra	1989
	M. P. Bhoj Open University, Bhopal	Madhya Pradesh	1991
	Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad	Gujarat	1994
	Karnataka State Open University, Mysore	Karnataka	1996
	Netaji Subhash Open University, Kolkata	West Bengal	1997
	U.P. Rajarshi Tandon Open University, Allahabad	Uttar Pradesh	1998
	Tamil Nadu Open University, Chennai	Tamil Nadu	2002

प्रो० रामबख्श सिंह वर्मा : आदरणीय सभापति महोदय, पहली सप्लीमेंटरी के "अ" भाग में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अब तक इन उपलब्ध 11 मुक्त विश्वविद्यालयों से कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? और, "ब" भाग में मैं यह जानना चाहूंगा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में जिन आठ राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को खोलने का प्रावधान है, उन्हें किन-किन राज्यों में खोलने का प्रस्ताव है?

डा० मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, अभी तक इस समय कुल 18 लाख छात्र इन मुक्त विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें लगभग 10 लाख छात्र तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं और 8 लाख छात्र दूसरे विभिन्न मुक्त विश्वविद्यालयों से। इसमें 2 लाख छात्रों ने इस साल एन.आई.ओ.एस., नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूल में प्रवेश लिया है और 3 लाख के करीब ने इग्नु में इस वर्ष प्रवेश लिया है। बाकी जिन राज्यों से हमारे पास सलाह आई है, उनमें केरल ने, उड़ीसा ने, हरियाणा ने और असम ने इस बारे में अपनी कुछ मंशा जाहिर की है, लेकिन केवल उड़ीसा ने ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा की है कि वह इसको बनाना चाहते हैं।

प्रो० रामबख्श सिंह वर्मा : सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा अन्य राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों का लाभ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को भी प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार ने क्या कोई विशेष प्रयत्न किए हैं? यदि किए हैं, तो उनका ब्यौरा मंत्री जी देने की कृपा करें।

डा० मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, यह सभी विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ और सुदूरस्थ सभी केन्द्रों में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और इनमें कहीं से भी कहीं के विद्यार्थी संलग्न हो सकते हैं। इसमें यह तो प्रश्न ही नहीं है कि उनके लिए कहीं पर कोई अभाव है। जहां से भी वे संलग्न होना चाहें, हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा ज्ञान-वाणी, ज्ञान-दर्शन तथा एकलव्य, ये तीन और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें ज्ञान-वाणी रेडियो के माध्यम से है। एफ०एम० रेडियो चैनल के माध्यम से अनेक राज्यों में इसके केन्द्र बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं, 80 के करीब केन्द्र इसमें खोलने का प्रस्ताव है, कुछ राज्यों में यह केन्द्र खुल चुके हैं। ज्ञान-दर्शन में टेलीविजन के माध्यम से निरंतर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और जो भी उन चैनलों का इस्तेमाल करना चाहें उसको वे कर सकते हैं। एकलव्य एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसको अभी 26 जनवरी को हमने संचालित किया है, उसमें तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम प्रचालित किए जाते हैं। इस प्रकार से कोई भी क्षेत्र आज वंचित नहीं है। जहां से भी छात्र लाभ लेना चाहें, ले सकते हैं।

SHRI FALI S. NARIMAN : Sir, it is very heartening to know from the hon. Minister that 18,00,000 students are participating in this venture. In our country, at least, where it is very difficult for people to get admission into established universities, it is very good. Sir, my question is: Is there any coordination between the State open universities and the Central Indira Gandhi Open University for maintaining excellence and improving standards in education? And, is there any improved communication network to stimulate greater interest, apart from television, which the hon. Minister mentioned?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, the general policy about this is that the Indira Gandhi National Open University prescribes courses, and these universities also prescribe courses. They, usually, interact quite frequently; conferences are held, meetings are held, where they exchange views. But the problem of maintaining the quality is a slightly difficult problem, because those who conduct the correspondence courses in these universities are not in direct touch with the Indira Gandhi National Open University. However, from time to time, the Indira Gandhi National Open University has made attempts to bring them together on non-formal basis, and on informal basis, and discuss things. We are now trying to establish a very important network by requesting ISRO to provide us with an educational satellite. Thereafter, the networking will be complete and every place in this country would be connected through satellite connections in a very positive, and in a very elaborate manner.

SHRI EKANATH K. THAKUR : Mr. Chairman, Sir, apart from the recognised open universities, there are several other universities which claim themselves to be open universities. They are flourshing in India. There are many unrecognised universities which carry the title of 'Universities' or 'Vidyapeeths'. May I ask, through your goodself, Sir, the hon. Minister whether there is any proposal to amend the Universities Act to see that the term 'University' or 'Vidyapeeth' is not used unauthorisedly and, thereby, the present kind of awarding degrees and diplomas—a large number of students have been cheated—is stopped immediately?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, there is enough provision even now to stop the use of the word 'University' by any unauthorised institution. No institution which is not recognised by a State or by the Central Government can use the word 'University'.

DR. P.C. ALEXANDER : Mr. Chairman, Sir, while noting the fact that eight new open universities are going to be established in the current Five

Year Plan, may I ask the hon. Minister whether he is satisfied that the number of universities is adequate to meet the growing demands for education from the people? If not so, would he consider some positive measures to encourage the State Governments to start much larger number of open universities in the Five Year Plan Period? My second question alongwith that, Sir, is whether he would take care to ensure that the open universities, do not function merely as a replication of the existing universities,and whether they would take care to provide courses and syllabi which would be more relevant to the needs/requirements of the types of students who come to these universities—I mean, the job-oriented courses. In this connection, may I even suggest to the hon. Minister to recommend the Yashwant Rao Chavan University at Nasik as one of the models for this purpose which they could emulate.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, we have a very set norm along which any State Government can open an open University, that is, the State Government which wants to establish an open University should provide at least Rs. 5 crores. And, in the first place, provision should also be made for 25 staff positions. The infrastructure should include a minimum of 6,000 sq. mts. of building span, and a network of minimum five study centres. We provide Rs. 2 crores immediate grant to such a proposal, if we receive. As regards the courses, you should be happy that the Indira Gandhi National Open University has already started an Ekalavaya channel on technical subjects. Some of these open universities are also giving instructions on technical subjects but not of a very high order, because the technical subjects require a practical training, and, for that, very strong infrastructure and linkages have to be created. That depends upon the State Governments as to whether they are willing to provide such a linkage or not. If they can provide, well, this will be a very good thing. However, we are trying to use the services of EDUSAT, as and when it is given to us, to give instructions in all subjects including technical subjects. Even now, with the Ekalavaya Programme, we are trying to coordinate in such a manner that the technical subjects are taught through television and practical training is given in certain recognised institutions, but the number is still low.

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस देश की बहुत सारी ऐसी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति जैसी होनी चाहिए , वैसी नहीं है यानी उनकी आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति ठीक

नहीं है ? ऐसी कितनी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन ओपन यूनिवर्सिटीज़ की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को छोड़कर शेष सब ओपन यूनिवर्सिटीज़ राज्य सरकारों की हैं। इस संबंध में सम्मानित सदस्य यदि मुझे कोई जानकारी देंगे तो मैं संबंधित राज्य सरकारों को भेजकर उनसे आग्रह करूंगा कि वे उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें।

SHRI K. NATWAR SINGH : Sir, the hon. Minister mentioned about the satellite channel which would link the Indira Gandhi National Open University. I want to know from the hon. Minister when will this be operational.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, this has been accepted in principle; and has now been accepted by the ISRO also. They are on the job. But, this requires a very strong infrastructure in the various States. We are talking with the States and their machinery to give us a firm commitment about these stations to receive signals and to transmit them in future. We can provide a satellite, we can provide the courses; but, the job of transmitting them has to be supported by the State Governments. So, as soon as this infrastructure is ready, this will be done; and, I hope that some of the States have shown very keen interest in it; and they are now estimating about the cost and the proper places where these transmitting centres would be established. As soon as this report is received, it will be done.

*506. [The Questioner (Shri S.S. Ahluwalia) was absent. For answer *vide* pages 39-40 *infra.*]

Damaged Rail Lines

*507. SHRI AHMED PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) total length of metre gauge rail lines in terms of route kilometres in Gujarat at present;

(b) what are the area-wise details of such lines;

(c) whether some of these lines are lying damaged for quite long;

(d) if so, the details thereof; and